(iii) Bank attested proforma invoice.

(iv) Photostat copy of Registration-cum-Membership certificate from the concerned Export Promotion Council to ensure that he is a registered exporter.

(b) Cash Compensatory Support is not paid with reference to loss or gain in foreign exchange but paid towards unrefunded taxes on exported goods.

(c) Does not arise.

Number of Subjects taught in Central Schools

1278. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that six subjects are being taught in Class IX of the Kendriya Vidyalayas whereas only five subjects are prescribed in Class X;

(b) whether it is also a fact that only five subjects are being taught in Government Schools in Class IX; and

(c) if the answers to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the reasons for the different number of subject being taught and the steps proposed to be taken to remove the anomaly?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir, so far as schools administered by the Delhi Administration are concerned.

(c) Sanskrit is being taught in Kendriya Vidyalayas up to class IX keeping in view the interest of students and to cover the teaching of Sanskrit satisfactorily for five years from class V to IX in view of its linguistic and cultural importance.

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद की रिक्तियों की संख्या

1279. **श्रीमती सुषमा स्वराज:** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए क्या न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) :

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायलयों में 1-7-1991 को न्यायाधीशों के रिक्त पदों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद भरने के लिए *सांविधानिक प्राधिकारियों* के बीच परामर्श की प्रक्रिया चल रही है ।

(ग) 9-5-1986 से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 18 से बढ़ाकर 26 कर दी गई है। कार्यभार में वृद्धि को देखते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थायी/अपर न्यायाधीशों के 53 नए पद सृजित करने का विनिश्चय किया गया है।

विवरण

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या

क्रम सं०	उच्च न्यायालय	ता० 1-7-91 को न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या
1.	इलाहाबाद	5
2.	आन्ध्र प्रदेश	5
3.	मुंबई	7
4.	कलकत्ता	5
5.	दिल्ली	1
6.	गुवाहाटी	2
7.	गुजरात	—
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू-कश्मीर	—
10.	कर्नाटक	4
11.	केरल	2
12.	मध्य प्रदेश	6
13.	मद्रास	3
14.	उड़ीसा	—
15.	पटना	6
16.	पंजाब और हरियाणा	1
17.	राजस्थान	3
18.	सिक्किम	1
	योग	52
	उच्चतम न्यायालय	3

Demand made by Bombay Bullion Association for bringing Gold by NRIs in the Country

1280. SHRI JOHN F. FERNANDES: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the demand made by Bombay Bullion Association that N.R.Is should be permitted to import periodically gold from abroad on payment of 25 per cent import duty to stop the influence of smuggled gold and to conserve our foreign exchange; and

(b) what is the Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) Such suggestions for allowing NRIs to bring or send gold into India would be considered in the context of Finance Minister's statement in the Budget speech that a comprehensive review of policies and procedures bearing on Non-resident Indian investments will be carried out.